

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 24-12-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Wednesday, 24 Dec, 2025

Edition : International Table of Contents

पेज 01 पाठ्यक्रम: जीएस 3:	भारत पहली आतंकवाद विरोधी नीति को अंतिम रूप दे रहा है
पेज 06 पाठ्यक्रम : सामान्य सूचना : 3 : आंतरिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था	'राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण खनिज'
पेज 07 पाठ्यक्रम: जीएस 3: पर्यावरण /	राइनो डीहॉर्निंग ने अफ्रीकी भंडार में अवैध शिकार को लगभग समाप्त कर दिया: अध्ययन
पेज 08 सिलेबस : जीएस 2 : शासन	शोषण को खत्म करें बाल तस्करी के लिए सरकार और नागरिक समाज से ठोस कार्रवाई की जरूरत है
पेज 09 पाठ्यक्रम : जीएस 1 : भारतीय समाज	अपस्क्रिलिंग गैप: एआई द्वारा महिलाओं को पीछे छोड़ने का जोखिम क्यों है
पृष्ठ 08 : संपादकीय विश्लेषण सिलेबस : जीएस 2 : शासन	वीबी-जी रैम जी अधिनियम 2025 संरचनात्मक कमियों को ठीक करता है

पृष्ठ 01 : जीएस 3 : आंतरिक सुरक्षा

भारत अपनी पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जो सभी राज्यों में आतंकवाद को रोकने, प्रतिक्रिया देने और मुकदमा चलाने के लिए एक समान, संस्थागत ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जैसी एजेंसियों के इनपुट के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेतृत्व में यह पहल, विशेष रूप से डिजिटल और अंतरराष्ट्रीय डोमेन में भारत की उभरती आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाती है।

India finalising first anti-terror policy

Vijaita Singh

NEW DELHI

The Union government is finalising India's first anti-terror policy to provide a template for all States to combat and respond to terror attacks and related incidents, a senior government official has told *The Hindu*.

Digital radicalisation, the misuse of open borders, and conversion networks funded by foreign players are among the key issues being discussed in the run-up to the policy's release.

The National Investigation Agency (NIA) is also

Key issues include digital radicalisation, the misuse of open borders, and conversion networks

organising an anti-terror conference on December 26 and 27 at Delhi where the contours of the policy are likely to be shared.

'NIA has given inputs'

"The Home Ministry is finalising the document and the NIA has also given its inputs," an NIA official told *The Hindu*.

Union Home Minister Amit Shah had announced

last November that a National Counter Terrorism Policy and Strategy would be introduced soon.

After the April 22 Pahalgam terror attack, the NIA had conducted meetings with anti-terror units of all States and apprised them of the measures to be put in place to prevent and pre-empt such attacks.

The use of the National Intelligence Grid (NAT-GRID), a secure platform for law enforcement agencies to access government and other databases, has also been discussed.

Over the past few months, NIA Director General Sadanand Date and

National Security Guard chief Brighu Srinivasan have briefed a few State police chiefs on issues such as foreign-funded conversion rackets, online radicalisation, and Aadhaar spoofing, among others.

Police against LWE

A National Policy and Action Plan for Left Wing Extremism (LWE) had earlier been introduced in 2015.

An Uttar Pradesh police official said that online radicalisation and the misuse of the open border with Nepal have been flagged as priority issues likely to find mention in the new anti-terror policy.

प्रस्तावित नीति की मुख्य विशेषताएं

- घटना-आधारित से निवारक दृष्टिकोण में बदलाव
 - हमले के बाद की प्रतिक्रिया के बजाय पूर्व-खालीपन, प्रारंभिक पहचान और व्यवधान पर जोर।
 - पहलगाम घटना जैसे हाल के हमलों से सबक लेता है।

नए युग के आतंकवाद चालकों पर ध्यान दें

- सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल कट्टरता।
 - आधार स्पूफिंग और पहचान धोखाधड़ी स्लीपर सेल को सक्षम बनाती है।
 - विदेशी वित्त पोषित रूपांतरण नेटवर्क कट्टरपंथ के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
 - खुली सीमाओं, विशेष रूप से भारत-नेपाल सीमा का दुरुपयोग, जो छिद्रपूर्ण सीमा कमजोरियों को उजागर करता है।

संघीय समन्वय को मजबूत करना

- यह नीति राज्यों के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करने का प्रयास करती है, संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को सुनिश्चित करती है।
- राज्य आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस), केंद्रीय एजेंसियों और खुफिया निकायों के बीच नियमित समन्वय।

एनआईए और एनएसजी की संस्थागत भूमिका

- एनआईए से प्राप्त जानकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के परिचालन दृष्टिकोण सामरिक और कानूनी आयामों को मजबूत करते हैं।
- प्रस्तावित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन ज्ञान-साझाकरण और क्षमता निर्माण को संस्थागत बनाता है।

प्रौद्योगिकी और डेटा एकीकरण का लाभ उठाना

- बहु-क्षेत्रीय डेटाबेस तक वास्तविक समय तक पहुंच के लिए राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड का उपयोग बढ़ाना।
- खुफिया नेतृत्व वाली पुलिसिंग की ओर एक कदम का संकेत देता है।

मौजूदा सुरक्षा ढांचे के साथ निरंतरता

- वामपंथी उग्रवाद पर राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015) पर आधारित है, जिसमें विकास और शासन सुधारों के साथ सुरक्षा संचालन शामिल हैं।
- क्षेत्र-विशिष्ट खतरों से परे एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत को इंगित करता है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

नागरिक स्वतंत्रता: विस्तारित निगरानी और डेटा पहुंच को गोपनीयता सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

कार्यान्वयन अंतर: विभिन्न क्षमताओं वाले राज्यों द्वारा एक समान रूप से अपनाया चिंता का विषय बना हुआ है।

सीमा पार सहयोग: खुली सीमाओं को संबोधित करने के लिए पड़ोसियों के साथ निरंतर राजनयिक और परिचालन समन्वय की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

प्रस्तावित राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना में एक रणनीतिक विकास का प्रतीक है, जो खंडित प्रतिक्रियाओं से एक सुसंगत, दूरदर्शी राष्ट्रीय ढांचे की ओर बढ़ रही है। डिजिटल कट्टरता, सीमा पार कमजोरियों और संस्थागत समन्वय को संबोधित करके, नीति भारत की आतंकवाद-विरोधी रणनीति को समकालीन खतरे की वास्तविकताओं के साथ संरेखित करती है। हालांकि, इसकी प्रभावशीलता अंततः मजबूत कार्यान्वयन, अंतर-एजेंसी विश्वास और संवैधानिक मूल्यों के साथ सुरक्षा के सावधानीपूर्वक संतुलन पर निर्भर करेगी, जिससे यह भारत के लोकतांत्रिक सुरक्षा प्रतिमान के लिए एक महत्वपूर्ण विकास बन जाएगा।

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : भारत की प्रस्तावित राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य आतंकवादी घटनाओं को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए सभी राज्यों को एक समान ढांचा प्रदान करना है।
2. इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह एक नई केंद्रीय आतंकवाद रोधी एजेंसी के निर्माण का प्रस्ताव है।
3. यह खुफिया नेतृत्व वाली पुलिसिंग के लिए नेटग्रिड जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के उपयोग पर जोर देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 1
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर : a)

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न : भारत अपनी पहली राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। प्रस्तावित नीति की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें और देखें कि यह डिजिटल युग में उभरती आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान कैसे करती है।

(150 शब्द)

पृष्ठ 06 : साझी : 3 : आंतरिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था

भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति में, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने इस बात को रेखांकित किया कि महत्वपूर्ण खनिज राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा तैयारियों और तकनीकी संप्रभुता के केंद्र में हैं। उनकी टिप्पणी इस बढ़ती मान्यता को दर्शाती है कि आधुनिक युद्ध, उन्नत विनिर्माण और भविष्य की प्रौद्योगिकियां रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों के एक संकीर्ण सेट तक सुनिश्चित पहुंच पर गहराई से निर्भर हैं।

‘Critical minerals important for national security and technological sovereignty’

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Critical minerals are crucial for national security, defence capability development, and technological sovereignty, Air Marshal Ashutosh Dixit, Chief of Integrated Defence Staff to the Chairman Chiefs of Staff Committee, said on Tuesday.

Speaking at a discussion titled “Minerals that Matter: Geopolitics, Sovereignty and Value Chains”, Air Marshal Dixit underscored the role of critical minerals in modern defence systems. “Modern defence systems, including jet engines, missiles, precision munitions, radars, satellites, batteries and semiconductors, are intrinsically dependent on assured access to these minerals,”



Air Marshal Ashutosh Dixit

he said. Highlighting the geopolitical dimensions of mineral supply chains, he said that global supply networks for critical minerals are highly concentrated and increasingly subject to export controls and geopolitical pressures.

He emphasised that self-reliant defence manufacturing and sustained operational readiness are inseparable from secure and

resilient mineral supply chains.

Referring to recent initiatives, Air Marshal Dixit highlighted the identification of critical minerals, the launch of the National Critical Mineral Mission, and government efforts to strengthen the value chain – from extraction and processing to manufacturing and recycling.

These measures, he said, are vital for translating policy intent into tangible outcomes.

The Air Marshal, who was speaking at the event organised by the Centre for Joint Warfare Studies and IP Bazaar, inaugurated a compilation of 30 technical reports on critical minerals, featuring detailed intellectual property landscape studies and market analyses.

महत्वपूर्ण खनिज क्यों मायने रखते हैं

रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा आयाम

- जेट इंजन, मिसाइल, रडार, उपग्रह, बैटरी और अर्धचालक जैसे आधुनिक रक्षा प्लेटफॉर्म लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, गैलियम और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।
- आपूर्ति श्रृंखलाओं में कोई भी व्यवधान परिचालन तत्परता और स्वदेशी रक्षा निर्माण को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है।

खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं की भू-राजनीति

- महत्वपूर्ण खनिजों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं कुछ देशों में अत्यधिक केंद्रित हैं, जिससे वे निर्यात नियंत्रण, भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और रणनीतिक दबाव के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
- यह ऊर्जा या सेमीकंडक्टर भू-राजनीति के समान "आपूर्ति श्रृंखलाओं के हथियारीकरण" की उभरती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

तकनीकी संप्रभुता

- उभरते क्षेत्रों - इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों, एआई हार्डवेयर और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स - को सुरक्षित खनिज पहुंच की आवश्यकता होती है।
- बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता आत्मनिर्भर भारत और प्रौद्योगिकी-संचालित शक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को कमजोर करती है।

नीति और संस्थागत प्रतिक्रियाएं

महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान

- भारत ने औपचारिक रूप से आर्थिक और रणनीतिक जरूरतों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची की पहचान की है, जो नीति को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करता है।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम)

- मिशन का उद्देश्य अन्वेषण और खनन से लेकर प्रसंस्करण, विनिर्माण और पुनर्चक्रण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।
- यह दृष्टिकोण मानता है कि अकेले खनन अपर्याप्त है; डाउनस्ट्रीम क्षमताएं वास्तविक रणनीतिक नियंत्रण निर्धारित करती हैं।

ज्ञान और क्षमता निर्माण

- कार्यक्रम में उद्घाटन किए गए महत्वपूर्ण खनिजों पर तकनीकी रिपोर्ट का संकलन, बौद्धिक संपदा मानचित्रण, बाजार खुफिया और स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास पर जोर देने को दर्शाता है।
- सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज जैसे संस्थानों की भूमिका रणनीतिक योजना में बढ़ते नागरिक-सैन्य-शैक्षणिक इंटरफेस पर प्रकाश डालती है।

आगे की चुनौतियाँ

सीमित घरेलू भंडार: भारत के पास कई महत्वपूर्ण खनिजों का मामूली भंडार है, जिसके लिए विदेशी परिसंपत्ति अधिग्रहण और खनिज कूटनीति की आवश्यकता है।

पर्यावरण और सामाजिक चिंताएँ: खनन विस्तार को स्थिरता, आदिवासी अधिकारों और पारिस्थितिक संरक्षण को संतुलित करना चाहिए।

तकनीकी अंतराल: वैश्विक नेताओं की तुलना में प्रसंस्करण और शोधन क्षमताएं एक कमजोर कड़ी बनी हुई हैं।

निष्कर्ष

भारत के रक्षा नेतृत्व द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों पर जोर देना राष्ट्रीय सुरक्षा सोच में एक आदर्श बदलाव का संकेत देता है, जहां संसाधन सुरक्षा को सैन्य ताकत और तकनीकी नेतृत्व से अविभाज्य माना जाता है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहल नीतिगत इरादे से संरचनात्मक परिवर्तन की ओर एक कदम है। भारत के लिए, लचीली और विविध खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना न केवल रक्षा तत्परता के लिए बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बनाए रखने और तेजी से प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यवस्था में रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए भी आवश्यक होगा।

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न : महत्वपूर्ण खनिज राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी संप्रभुता के एक नए स्तंभ के रूप में उभरे हैं। इस संदर्भ में, भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के रणनीतिक महत्व की जांच करें। भारत को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें और दीर्घकालिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का मूल्यांकन करें।

साइंस में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन मजबूत अनुभवजन्य प्रमाण प्रदान करता है कि गैंडे के सींग हटाने से अफ्रीकी वन्यजीव भंडार में अवैध शिकार में नाटकीय कमी आई है। ऐसे समय में जब वैश्विक गैंडों की संख्या घटकर 28,000 से कम रह गई है, निष्कर्ष भारत और विश्व स्तर पर जैव विविधता शासन और पर्यावरण नीति की बहस के लिए प्रत्यक्ष प्रासंगिकता के साथ लागत प्रभावी, प्रोत्साहन-आधारित वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

Rhino dehorning nearly eliminated poaching in African reserves: study

Reserves that removed the horns of rhinos reported a 75% decrease in poaching compared to the pre-dehorning levels. In the seven reserves that implemented abrupt dehorning (within one to two months), poaching fell by 78%. Dehorned rhinos also faced a 95% lower risk of being poached compared to animals with intact horns

Sanjukta Mondal

Once upon a time, the thunder of the hooves of lakhs of mighty rhinoceroses echoed across the savannahs, grasslands, and tropical forests of Africa and Asia – but things have gotten pretty quiet lately. As of 2024, fewer than 28,000 rhinos remain on the planet, all five species combined.

Relentless poaching has been a major threat to the survival of rhinos around the world. Greater Kruger, the southern African reserves protecting the world's largest rhino population, alone lost 1,985 black and white rhinos between 2017 and 2023. That's nearly 6.5% of the rhino population disappearing each year, despite an investment of \$74 million in anti-poaching strategies, including ranger patrols, trained tracking dogs, AI-powered detection cameras, and aerial surveillance.

One approach that has shown promise is dehorning. An international team of researchers recently collected data over seven years from 11 reserves in the South African portion of the Greater Kruger region and found that dehorning significantly reduced poaching incidents by removing the primary incentive for poachers.

Nelson Mandela University senior lecturer and study member Tim Kuiper said the idea for their project arose from an urgent need on the ground: "The managers, rangers and scientists [at Kruger National Park] came together and asked a bold question: why are we still losing so many rhinos? What can we do differently?"

The team found that dehorning 2,284 rhinos across eight reserves resulted in a sudden 78% drop in poaching, achieved with just 1.2% of the total anti-poaching budget. The findings were published in *Science*.

Illegal rhino horns

Rhinoceroses' horns are made of keratin, the same fibrous protein found in hair and nails. The animals use them to dig to access edible plants and roots, and as a symbol of virility during mating.

Some people also perceive rhino horns as status symbols. Many practitioners of traditional medicine in certain Asian countries, but especially China and Vietnam, also include rhino horns in their preparations because they believe the horn treats everything from fever and gout to more mystical issues like possession. There is no scientific evidence to back any of these claims, but that has not stopped a global black market worth hundreds of millions of dollars still persists.



Rangers manage Quintus, a 3-year-old male white rhino, which has just been tranquillised at the Lewa Wildlife Conservancy, in Meru County, Kenya. REUTERS

One 2022 report by the Wildlife Justice Commission found that the wholesale trade in raw rhino horns between 2012 and 2022 generated between \$874 million and \$1.13 billion in gross illicit income.

Why poachers kill

The researchers behind the new study said the demand for rhino horns plus poverty in many local communities creates financial pressures that drive people to risk everything, sometimes their lives, to poach or support poachers.

To remove a rhino's horn without causing harm, conservationists and veterinarians sedate, blindfold, and fit the animal with earplugs to reduce stress. Then they carefully cut 90-93% of the horn with a saw, above the germinal layer, which is the living tissue at the horn's base that's essential for it to regrow. After trimming, the remaining stump is smoothed and coated with a tarry substance to prevent infections.

Poachers often operate under intense pressure, so killing the rhino allows them to remove the entire horn without resistance.

Dehorning against poaching

To assess the effectiveness of dehorning in reducing poaching, the researchers analysed quarterly data from 2017 to 2023 across 11 wildlife reserves. Using a powerful statistical method called hierarchical Bayesian regression modelling, they compared reserves that dehorned rhinos with those that didn't, tracking changes in poaching before and after the intervention.

Reserves that removed the horns reported a 75% drop in poaching versus

While arresting poachers remains a part of the anti-poaching toolkit, they weren't found to be as effective at deterring poachers. Researchers said this could be because systemic issues and corruption create loopholes that traffickers can exploit to avoid detection

pre-dehorning levels. In the seven reserves that implemented abrupt dehorning (within one to two months), poaching fell off by 78%. Dehorned rhinos also faced a 95% lower risk of being poached compared to those with intact horns.

In another striking finding, while efforts to detect and arrest poachers remain a crucial part of the anti-poaching toolkit, they weren't found to be as effective at actually deterring poachers. The researchers said this could be because systemic issues and corruption create loopholes that traffickers can exploit to avoid detection. Weak criminal justice systems also make it worse, often allowing poachers to escape with little or no meaningful punishment.

Conservation with locals

Kaziranga National Park in Assam, home to one of the world's largest populations of greater one-horned rhinos, has also suffered poaching.

Bibhab Kumar Talukdar, an International Union for Conservation of Nature awardee and rhino conservationist, said that while poaching still claims over 400 rhinos a year, India

and Nepal have lost only one or two over the last three years. Kaziranga's success has been attributed to smart patrolling and active community engagement. Partnerships of local communities and park authorities have helped mitigate human-wildlife conflict.

"So why should India or Nepal need dehorning?" Mr. Talukdar asked.

The efforts required extensive groundwork, involving more than 1,000 hours in workshops and discussions with reserve staff and rangers on how to collect and interpret data. The labour-intensive nature of such research highlights the need to involve those on the ground in conservation efforts. Rangers in particular are often locals and possess regional ecological knowledge, but this resource remains underutilised.

Dr. Kuiper said rangers are the frontline defenders of conservation. Their welfare, including fair pay, training, and safety, must be prioritised alongside interventions, as lasting success depends on supporting the people who implement these strategies.

The researchers also noted that while dehorning might not be a silver bullet, as poachers may still target rhinos for the small horn remnants, it shows strong potential as a long-term strategy. They believe the study's findings can help governments and wildlife protection agencies make more informed decisions about allocating resources and assessing the effectiveness of interventions.

(Sanjukta Mondal is a chemist-turned-science-writer with experience in writing popular science articles and scripts for STEM YouTube channels. sanjuktamondal.sm@gmail.com)

THE GIST

Greater Kruger lost 1,985 rhinos between 2017 and 2023. That was despite millions invested in anti-poaching strategies, including patrols, dogs, AI-powered cameras, and aerial surveillance. Now, one approach is showing promise — dehorning

Some perceive rhino horns as status symbols. They are also used in traditional medicine because it is believed that it treats everything from fever and gout to more mystical issues like possession. One report found that horns generated between \$874 million and \$1.13 billion in illicit income

India and Nepal, however, have chosen not to dehorn, because their local programmes have been successful. They have lost only one or two rhinos over the last three years. Kaziranga's success has been attributed to smart patrolling and community engagement

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

अवैध शिकार में उल्लेखनीय कमी

- डीहॉर्निंग को लागू करने वाले भंडारों में प्री-डीहॉर्निंग स्तरों की तुलना में अवैध शिकार में 75% की गिरावट देखी गई।
- भंडार में जहां तेजी से (1-2 महीने के भीतर) डीहॉर्निंग की गई थी, अवैध शिकार में 78% की गिरावट आई।
- सींग वाले गैंडों को बरकरार सींग वाले गैंडों की तुलना में अवैध शिकार होने का 95% कम जोखिम का सामना करना पड़ा।

उच्च लागत-प्रभावशीलता

- डीहॉर्निंग कुल अवैध शिकार विरोधी व्यय का केवल 1.2% था, फिर भी अनुपातहीन रूप से उच्च परिणाम दिए।
- इसके विपरीत, महंगे प्रवर्तन-भारी उपायों (एआई निगरानी, हवाई गश्त, डिटेक्शन डॉग्स) ने सीमित निरोध दिखाया।

प्रभावशीलता के पीछे तर्क

- अवैध शिकार मुख्य रूप से प्रोत्साहन-संचालित है; सींग को हटाने से मुख्य आर्थिक इनाम समाप्त हो जाता है।
- कमजोर आपराधिक न्याय प्रणाली, भ्रष्टाचार और छिद्रपूर्ण प्रवर्तन तस्करों को सजा से बचने की अनुमति देते हैं, जिससे अकेले गिरफ्तारी का निवारक प्रभाव कम हो जाता है।

व्यापक संदर्भ: वन्यजीव अपराध और अवैध बाजार

- केराटिन से बने राइनो सींगों का कोई सिद्ध औषधीय मूल्य नहीं है, फिर भी सांस्कृतिक मान्यताओं और स्थिति प्रतीकवाद के कारण अवैध बाजारों में उच्च कीमतों का आदेश देता है।
- वन्यजीव न्याय आयोग के अनुसार, अवैध गैंडे के सींग के व्यापार ने 2012 और 2022 के बीच \$874 मिलियन-\$1.13 बिलियन की कमाई की।
- स्थानीय समुदायों में गरीबी और वैकल्पिक आजीविका की कमी अवैध शिकार नेटवर्क के लिए धक्का कारकों के रूप में कार्य करती है।

सीमाएँ और नैतिक विचार

चांदी की गोली नहीं: शिकारी अभी भी अवशिष्ट सींग स्टंप के लिए गैंडों को मार सकते हैं।

पशु कल्याण संबंधी चिंताएं: हालांकि वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित और गैर-घातक, डीहॉर्निंग नैतिक बहस को जन्म देती है।

दीर्घकालिक स्थिरता: सींग के फिर से उगने पर समय-समय पर डीहॉर्निंग को दोहराया जाना चाहिए।

भारत के लिए सबक

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और नेपाल में गैंडों की रक्षा करने में भारत की सफलता का श्रेय स्मार्ट गश्त, मजबूत कानूनी प्रवर्तन और सामुदायिक भागीदारी को दिया जाता है।

- यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि संदर्भ मायने रखता है: रणनीतियों को यांत्रिक रूप से दोहराए जाने के बजाय स्थानीय पारिस्थितिक, सामाजिक और शासन स्थितियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

गैंडे के सींग निकालने पर अध्ययन साक्ष्य-आधारित और प्रोत्साहन-संवेदनशील संरक्षण रणनीतियों के महत्व को रेखांकित करता है। जबकि अफ्रीकी संदर्भों में सींग निकालना एक अत्यधिक प्रभावी और किफायती उपकरण साबित हुआ है, यह एक व्यापक सबक को भी पुष्ट करता है: वन्यजीव संरक्षण केवल सैन्यीकृत प्रवर्तन पर भरोसा नहीं कर सकता है। सतत परिणामों के लिए वैज्ञानिक हस्तक्षेप, मजबूत संस्थानों, सामुदायिक जुड़ाव और रेंजर कल्याण पर ध्यान देने के संतुलित मिश्रण की आवश्यकता होती है। नीति निर्माताओं के लिए, मुख्य टेकअवे प्रति सींग को अपनाने में नहीं है, बल्कि संदर्भ-विशिष्ट, डेटा-संचालित संरक्षण नीतियों को डिजाइन करने में है जो वन्यजीव अपराध के पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक दोनों चालकों को संबोधित करते हैं।

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: संरक्षण रणनीति के रूप में गैंडे के सींग निकालने के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राइनो सींग केराटिन से बने होते हैं, वही प्रोटीन जो मानव बालों और नाखूनों में पाया जाता है।
2. सींग हटाने से सींग पूरी तरह से हट जाता है, स्थायी रूप से इसके पुनर्विकास को रोका जा सकता है।
3. कुछ अफ्रीकी भंडारों में अवैध शिकार के लिए प्रोत्साहन को कम करने के लिए डीहॉर्निंग पाया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर : a)

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: "वन्यजीव संरक्षण रणनीतियों को आर्थिक प्रोत्साहनों को संबोधित करना चाहिए, न कि केवल प्रवर्तन। अफ्रीकी भंडार में गैंडों के सींग काटने पर हाल के अध्ययन के संदर्भ में इस कथन की चर्चा करें।

पृष्ठ 08 : जीएस 2 : शासन/प्रारंभिक

बाल तस्करी मानवाधिकारों और संवैधानिक नैतिकता के सबसे गंभीर उल्लंघनों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है, जो गुलामी के एक आधुनिक रूप के बराबर है। 19 दिसंबर के एक हालिया फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में बाल तस्करी को "गहरी परेशान करने वाली वास्तविकता" के रूप में वर्णित किया, जो एक विस्तृत कानूनी ढांचे के बावजूद बच्चों की पूरी तरह से रक्षा करने में समाज और संस्थानों की विफलता को रेखांकित करता है। बेंगलुरु में संगठित तस्करी नेटवर्क द्वारा एक नाबालिग के यौन शोषण से संबंधित मामले ने बाल तस्करी के संरचनात्मक, कानूनी और सामाजिक आयामों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ**अपराध की प्रकृति**

- न्यायालय ने माना कि बाल तस्करी और यौन शोषण गरिमा, शारीरिक अखंडता और बच्चों की सुरक्षा के संवैधानिक वादे के मूल में हमला करते हैं।
- इसने तस्करी को एक संगठित अपराध के रूप में मान्यता दी, जिसमें भर्ती, परिवहन, आश्रय और शोषण के स्तरित नेटवर्क शामिल थे।

पीड़ित-केंद्रित न्यायिक दृष्टिकोण

- पीठ ने एक बच्चे की गवाही दर्ज करते समय "संवेदनशीलता और अक्षांश" की आवश्यकता पर जोर दिया।
- गवाही में मामूली विसंगतियों को अविश्वास का आधार नहीं होना चाहिए, इसमें शामिल आघात को देखते हुए।
- एक तस्करी किया गया बच्चा, अदालत ने स्पष्ट किया, एक साथी नहीं है, बल्कि एक घायल गवाह है, जिसकी गवाही उच्च साक्ष्य मूल्य की हकदार है।

कानूनी पुष्टि

- अदालत ने अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिससे तस्करी से संबंधित अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए कानूनी आधार मजबूत हुआ।

शासन और कार्यान्वयन अंतराल**कम दोषसिद्धि दर**

- गृह मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 2018 और 2022 के बीच मानव तस्करी के 10,659 मामले सामने

End the exploitation

Child trafficking needs concerted action from government and civil society

One of the worst forms of modern slavery is child trafficking, and the Supreme Court of India has issued a stern wake-up call about the prevailing situation in India. In a December 19 judgment, it observed that child trafficking is a "deeply disturbing reality" in the country where sexual exploitation of children by organised cartels continues to flourish despite protective laws. It was hearing a case regarding a minor who was forcibly exploited sexually by a gang of traffickers in Bengaluru. The Court upheld the conviction of the gang members under the Immoral Traffic (Prevention) Act. The offence, it said, struck at the very foundations of dignity, bodily integrity and the state's constitutional promise of protection to every child against exploitation. A Bench of Justices Manoj Misra and Joymalya Bagchi drew attention to the complex and layered structure of organised crime networks which operate at various levels of recruiting, transporting, harbouring and exploiting minor victims. The Bench laid down guidelines to follow in child trafficking cases, particularly the need for "sensitivity and latitude" while hearing the child's testimony. It may not be possible for the child to narrate with precision and clarity the nature of the crime, it said, pointing out that courts must not disbelieve her testimony because of minor inconsistencies in her evidence.

A victim of sex trafficking, particularly a minor, is not an accomplice, it noted, and "her deposition is to be given due regard and credence as that of an injured witness". The Court's observations must not go in vain and the onus is on the government and civil society to do what is necessary to protect children. The net must be spread wide to end other forms of exploitation as well such as forced child labour. Stringent laws may be in place, but on the ground, much more needs to be done like giving teeth to anti-trafficking units or passing an anti-trafficking Bill. Last year, the Ministry of Home Affairs told Parliament that India had recorded as many as 10,659 cases of human trafficking between 2018 and 2022, but of the persons arrested for the crime in the same period, the conviction rate was just 4.8%. The issue of rehabilitation after rescue also has to be thought through; mere compensation is not enough. The focus must be on prevention and protection, and one way to ensure this is to keep children in school till they are 14 as the Right to Education Act promised. With the advent of the digital space, trafficking is a shape-shifting evil, and government and social entities must be prepared to tackle all its forms.

आए, लेकिन दोषसिद्धि दर केवल 4.8% है, जो कमजोर जांच, अभियोजन और गवाहों की सुरक्षा का संकेत देती है।

कमजोर संस्थागत क्षमता

- मानव तस्करी विरोधी इकाइयों में अक्सर पर्याप्त जनशक्ति, प्रशिक्षण और समन्वय की कमी होती है।
- एक व्यापक, स्टैंडअलोन तस्करी विरोधी कानून की अनुपस्थिति एक एकीकृत प्रतिक्रिया को सीमित करती है।

पुनर्वास घाटा

- बचाव के बाद पुनर्वास अविकसित बना हुआ है।
- अकेले मुआवजा अपर्याप्त है; दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक देखभाल, शिक्षा और आजीविका सहायता आवश्यक है।

आधारशिला के रूप में रोकथाम

सुरक्षा के रूप में शिक्षा: यह सुनिश्चित करना कि बच्चे कम से कम 14 साल तक स्कूल में रहें, जैसा कि **शिक्षा का अधिकार अधिनियम** के तहत परिकल्पित है, तस्करी और जबरन श्रम के प्रति संवेदनशीलता को कम करता है।

सामुदायिक और नागरिक समाज की भूमिका: जागरूकता, प्रारंभिक पहचान और सामाजिक सतर्कता महत्वपूर्ण हैं, खासकर स्रोत क्षेत्रों में।

डिजिटल आयाम: तस्करी का तेजी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाभ उठाने के साथ, कानून प्रवर्तन को साइबर-निगरानी और डिजिटल फोरेंसिक क्षमताओं को विकसित करना चाहिए।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक संवैधानिक चेतावनी है कि बाल तस्करी को केवल कानूनों के माध्यम से संबोधित नहीं किया जा सकता है। इस शोषण को समाप्त करने के लिए राज्य, न्यायपालिका और नागरिक समाज द्वारा ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है, जो दयालु पीड़ित-केंद्रित प्रक्रियाओं के साथ मजबूत प्रवर्तन का संयोजन है। शिक्षा, प्रभावी अभियोजन, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और समग्र पुनर्वास के माध्यम से रोकथाम भारत की प्रतिक्रिया के स्तंभ बनने चाहिए। एक ऐसे युग में जहां तस्करी तेजी से अनुकूल और डिजिटल होती जा रही है, बच्चों की सुरक्षा करना केवल एक कल्याणकारी दायित्व नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की परीक्षा है।

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : भारत में बाल तस्करी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. तस्करी के शिकार बच्चे को भारतीय आपराधिक कानून के तहत अपराध के साथी के रूप में माना जाता है।
2. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बाल पीड़ित की गवाही में मामूली विसंगतियां सबूतों को खारिज करने का आधार नहीं होनी चाहिए।
3. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम संगठित यौन शोषण पर मुकदमा चलाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 2 और 3 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर : a)

यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: कड़े कानूनों के बावजूद, भारत में मानव तस्करी के मामलों में दोषसिद्धि की दर बहुत कम है। कानून और परिणामों के बीच इस अंतर के कारणों का विश्लेषण करें। पीड़ित-केंद्रित न्यायिक दृष्टिकोण न्याय वितरण में कैसे सुधार कर सकता है? (250 शब्द)

जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) श्रम बाजारों को नया आकार दे रहा है, स्वचालन, उत्पादकता और कौशल के बारे में चिंताएं भारत के विकास प्रवचन के केंद्र बन गई हैं। हालांकि, एक महत्वपूर्ण लिंग आयाम को नजरअंदाज किए जाने का जोखिम है। भारत के समय उपयोग सर्वेक्षण (2024) पर आकर्षित, लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कामकाजी महिलाओं को भुगतान और अवैतनिक काम के दोहरे बोझ के कारण गंभीर समय की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें एआई-संचालित अर्थव्यवस्था में काफी नुकसान होता है जहां निरंतर कौशल बढ़ाना आवश्यक है। यह केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक संरचनात्मक आर्थिक और शासन की चुनौती है।

The upskilling gap: why women risk being left behind by AI

With 10 hours less per week for self-development than men, India's working women need flexible learning and "time-saving" policies to compete

DATA POINT

Shravani Prakash
Tanu M. Goyal
Chellsea Lauhka

As 2025 ends, Indians are consumed by two anxieties – whether artificial intelligence (AI) will take over their jobs, and whether the future belongs to 80-hour work weeks or the right to disconnect after office hours. But for millions of working women, a near 80-hour work week is already a lived reality, as their workday continues long after office hours, filled with unrecognised and unpaid labour. Unfortunately, no AI or algorithm has yet threatened to take over women's "unpaid work" or rescue them from the long hours spent on cooking, cleaning, caregiving, planning, and emotional management. India's latest Time Use Survey (2024) makes this reality unmistakable: 40% of women now participate in the labour force. They are not simply leaning into paid work; instead, they are working a relentless second shift. As women take on more paid work, their unpaid responsibilities hardly decline – instead of substitution, there is stacking. This results in working women being left with limited time for personal development, leisure, or adequate rest. **Chart 1** highlights a stark imbalance in how Indian men and women divide their working hours. On average, working women spend around 9.6 hours a day on combined paid and unpaid work. A substantial share of this time is, however, spent on unpaid work that largely comprises elderly and childcare activities; domestic chores such as cooking and cleaning; and other voluntary work and subsistence production. This burden peaks when women are in their prime ages (25-39 years), leading to their total working hours exceeding 70 hours a week. In contrast, men record lower

total hours of work. On average, they spend about 8.6 hours a day on combined paid and unpaid work, with more than 80% of this time devoted to paid activities (wage/salaried work, remunerative self-employment, and production of goods and services for sale). Across the working life cycle, men's total work hours typically fall within the range of 54-60 hours per week, largely because their unpaid workload is minimal and stable across life stages. Women's working hours exceed men's across nearly every age group. The gap is widest in the 25-39 age range, when women spend double the time on unpaid caregiving than men, with childcare forming the largest component. Even later in life, while men's unpaid contributions rise marginally (often to care for ageing parents), the broader unequal contract at home remains intact, regardless of age, occupation, or income level. Women don't have more hours in a day, but they simply offset the burden of double shifts by cutting back on time for self-care. On average, women in India sleep fewer hours in a week than men, with the gap widening to around 2.2.5 hours a week during their prime working years (**Chart 2**). Women, on average, also spend 10 hours less than men every week on self-development activities, including learning, skill enhancement, building self-awareness and practices that support mental, emotional, and physical well-being. Once again, this gap is widest (around 11-12 hours per week) during the prime age group. These figures matter immensely in an AI-disrupted economy, since time for upskilling and self-development is essential to transition from low-skilled to higher-value work. Women contribute a mere 17% of India's GDP, not because they do too little but because much of their essential labour is unpaid and invisible, which does not get added in national income calculations. The Periodic Labour Force

Survey shows that nearly 40% of women outside the labour market cite household responsibilities as the reason. Even the recent rise in women's workforce participation is driven largely by unpaid family work and low-paid self-employment. The AI era could make this worse, as women's jobs are more automation-prone, and AI-driven performance metrics risk penalising caregivers whose time constraints remain invisible to algorithms. True empowerment cannot mean merely adding jobs, unless paid employment replaces women's drudgery instead of compounding it. Policy, technology, and workplaces must be redesigned around women's time – an undervalued resource that underpins both care and productivity. These must shift towards an outcome-based approach that explicitly uses time-use data to free women's time from unpaid work and redirect it toward higher-value, remunerative activities. The gender budget can be a key tool to enable this by integrating time-use metrics. Budgets must prioritise and sustain outlays to time-saving infrastructure such as affordable childcare and elderly care, piped water, clean energy, and safe public transport. Simultaneously, to adapt and thrive in a rapidly changing world of work, women must have access to lifelong and flexible upskilling opportunities designed around their time, mobility, and digital constraints. This calls for sustained gender budget allocations to expand programmes that build locally relevant vocational capabilities, strengthen technology and digital skills, and scale targeted initiatives such as the India AI Mission and AI Careers for Women programmes. Until women's time is valued, freed, and mainstreamed into policy and growth strategy, India's 2047 Viksit Bharat vision will remain constrained by women's invisible labour, time poverty and underutilised potential.

Double shift for women

Chart 1A: Working hours for men in a day across age groups

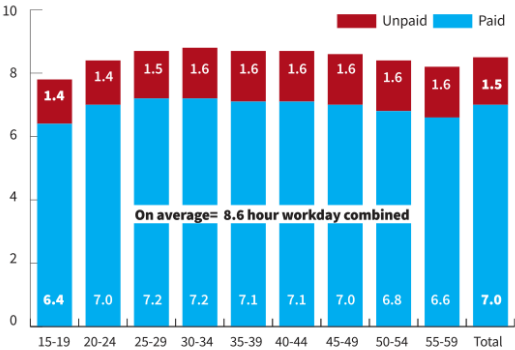


Chart 1B: Working hours for women in a day across age groups

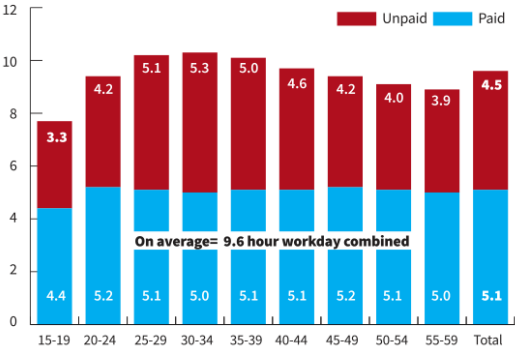
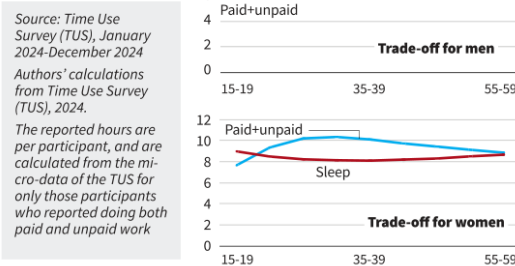


Chart 2: Trade-off between work and sleep in number of hours across age groups



Source: Time Use Survey (TUS), January 2024-December 2024
Authors' calculations from Time Use Survey (TUS), 2024.
The reported hours are per participant, and are calculated from the micro-data of the TUS for only those participants who reported doing both paid and unpaid work

मुख्य तर्क और साक्ष्य

काम और समय की गरीबी का दोहरा बोझ

- भारत में कामकाजी महिलाएं संयुक्त भुगतान और अवैतनिक काम पर प्रति दिन लगभग 9.6 घंटे खर्च करती हैं, जबकि पुरुषों के लिए यह 8.6 घंटे है।
- महिलाओं का अवैतनिक काम - देखभाल करना, घरेलू काम और भावनात्मक श्रम - में गिरावट नहीं आती है क्योंकि वे भुगतान किए गए रोजगार में प्रवेश करते हैं; इसके बजाय, जिम्मेदारियां विकल्प के बजाय "ढेर" हो जाती हैं।
- बोझ 25-39 वर्षों के दौरान चरम पर होता है, जब महिलाएं प्रति सप्ताह 70 घंटे से अधिक काम करती हैं, जो पुरुषों की तुलना में काफी अधिक है।

अपस्क्रिलिंग और स्व-विकास अंतर

- महिलाएं आत्म-विकास, सीखने और कौशल बढ़ाने पर पुरुषों की तुलना में प्रति सप्ताह लगभग 10 घंटे कम खर्च करती हैं।
- यह अंतर प्रमुख कामकाजी वर्षों के दौरान प्रति सप्ताह 11-12 घंटे तक बढ़ जाता है, ठीक उसी समय जब करियर की प्रगति और अपस्क्रिलिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है।
- एआई-बाधित अर्थव्यवस्था में, रीस्किलिंग के लिए समय तक सीमित पहुंच से महिलाओं के कम-कुशल, कम-वेतन और स्वचालन-प्रवण नौकरियों में फंसने का खतरा बढ़ जाता है।

आर्थिक निहितार्थ

- भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महिलाएं केवल 17% का योगदान देती हैं, कम प्रयास के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके श्रम का एक बड़ा हिस्सा अवैतनिक है और राष्ट्रीय आय लेखांकन से बाहर रखा गया है।
 - आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से पता चलता है कि श्रम बल के बाहर की लगभग 40% महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों को मुख्य कारण बताती हैं।
- महिला श्रम बल की बढ़ती भागीदारी अक्सर अवैतनिक पारिवारिक काम या कमजोर स्वरोजगार से प्रेरित होती है, जो सीमित आय सुरक्षा प्रदान करती है।

एआई और लैंगिक जोखिम

- महिलाओं की नौकरियां स्वचालन के लिए अतिसंवेदनशील होती हैं, जबकि एआई-संचालित प्रदर्शन मेट्रिक्स देखभाल करने वालों को दंडित कर सकते हैं जिनकी समय की कमी एल्गोरिदम के लिए अदृश्य है।
- सुधारात्मक नीतियों के बिना, एआई मौजूदा लैंगिक असमानताओं को कम करने के बजाय उन्हें मजबूत कर सकता है।

नीति और शासन आयाम

विकास और रोजगार पर पुनर्विचार

- सच्चा सशक्तिकरण केवल भुगतान वाली नौकरियों को जोड़ने से नहीं आ सकता है यदि अवैतनिक कठिन परिश्रम अपरिवर्तित रहता है।
- उच्च-मूल्य वाली गतिविधियों के लिए महिलाओं के समय को मुक्त करने के लिए समय-उपयोग डेटा पर आधारित एक परिणाम-आधारित नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

लिंग बजट की भूमिका

- लिंग बजटिंग निवेश को प्राथमिकता देने के लिए समय-उपयोग मेट्रिक्स को एकीकृत कर सकता है:
 - सस्ती चाइल्डकेअर और बुजुर्गों की देखभाल
 - पाइप से पानी और स्वच्छ ऊर्जा
 - सुरक्षित और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन
- ये "समय बचाने वाले बुनियादी ढांचे" कुशल कार्य में भाग लेने के लिए महिलाओं की क्षमता को सीधे बढ़ाते हैं।

लचीला और आजीवन अपस्क्रिलिंग

- महिलाओं को अपने समय और गतिशीलता की कमी के अनुरूप लचीले, मॉड्यूलर और स्थानीय रूप से सुलभ शिक्षण मॉडल की आवश्यकता होती है।
- महिलाओं के लिए इंडिया एआई मिशन और एआई करियर कार्यक्रम जैसी लक्षित पहल सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, लेकिन इसके लिए निरंतर धन और पैमाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

लेख इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं की समय की गरीबी भारत की एआई तत्परता और दीर्घकालिक विकास पर एक बाधकारी बाधा है। अवैतनिक देखभाल कार्य को पहचानने, कम करने और पुनर्वितरित किए बिना, कौशल और तकनीकी नेतृत्व के उद्देश्य से नीतियां अधूरी रहेंगी। लिंग-उत्तरदायी बजट, समय बचाने वाले बुनियादी ढांचे और लचीले अपस्क्रिलिंग इकोसिस्टम के माध्यम से महिलाओं के समय का मूल्यांकन करना आवश्यक है। यदि भारत के विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण को साकार करना है, तो महिलाओं को एआई क्रांति की निष्क्रिय दर्शक नहीं बनना चाहिए, बल्कि सशक्त प्रतिभागियों को सशक्त बनाना चाहिए - जो उन नीतियों द्वारा सक्षम हैं जो समय को निजी बोझ के रूप में नहीं, बल्कि सार्वजनिक नीति प्राथमिकता के रूप में देखती हैं।

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न : "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, महिलाओं को अवैतनिक देखभाल कार्य और समय की गरीबी के बोझ के कारण असंगत अपस्क्रिलिंग नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस कथन की चर्चा भारत द्वारा समय-उपयोग डेटा का उपयोग करने के संदर्भ में कीजिए। श्रम बल की भागीदारी, तकनीकी संप्रभुता और समावेशी विकास के लिए निहितार्थों की जांच करें। एआई-संचालित अर्थव्यवस्था में लिंग-समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं। (250 शब्द)

The VB-G RAM G Act 2025 fixes structural gaps

The President of India has assented to the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin) Act, 2025, enhancing the statutory wage employment guarantee to 125 days and strengthening rural livelihoods through empowerment, convergence, and saturation-based delivery for a resilient, self-reliant rural Bharat.

A misreading by some
Yet, even as the VB-G RAM G Act comes into force, there are some who have advanced a set of assumptions that do not withstand careful scrutiny. It is being claimed that the employment guarantee has been weakened, that decentralisation and demand-based rights have been undermined without consultation, and that the reform represents fiscal withdrawal that is disguised as restructuring. Each of these assertions rests on a misreading of the Act's substance and intent.

What has led to this misreading is a deeper conceptual error – the assumption that welfare and development are opposing choices. The new framework is built on the opposite understanding: that welfare, anchored in an enhanced statutory livelihood guarantee, and development, anchored in durable infrastructure creation and productivity enhancement, are mutually reinforcing. Income support, asset creation, agricultural stability and long-term rural productivity are treated as a continuum rather than a trade-off. This is not aspirational rhetoric but an approach embedded in statutory design.

The suggestion that the legal right to employment has been diluted is incorrect. The Act retains the statutory and justiciable character of the employment guarantee while strengthening its enforceability. Far from being curtailed, the entitlement has been expanded from 100 to 125 days. Procedural dis-entitlement clauses that previously nullified unemployment allowance in practice have been removed, and time-bound grievance redress mechanisms have been reinforced. The reform directly addresses the long-recognised gap between statutory promise and lived reality.

It is also argued that demand-based employment has been abandoned in favour of top-down planning. This rests on a false binary. Demand for work continues to originate from workers. What changes is that demand is no longer addressed only after distress has set in. By anchoring execution in advance, participatory village-level planning, the reform ensures that when workers seek employment, work is actually available rather than denied due to administrative unpreparedness. Planning, in this sense, does not suppress demand; it operationalises it.

The change of centralisation overlooks the architecture of the law. Gram panchayats remain the primary planning and implementing authorities, and gram sabhas retain approval powers over local plans. What has changed is that decentralised planning is no longer ad hoc or episodic but institutionalised as a structured and participatory process. Viksit Gram Panchayat Plans are aggregated at the block, district, State and national levels to enable coordination, convergence and visibility across sectors, not to



Shivravi Singh Chouhan
is Union Minister for Agriculture and Farmers' Welfare, and Rural Development, Government of India

override local priorities. What is centralised is coherence; the decision-making authority remains local. This corrects fragmentation without undermining decentralisation.

Claims that the reform was pushed through without consultation are equally inconsistent with the record. The Bill was preceded by extensive consultations with State governments, technical workshops and multi-stakeholder discussions. Core design features – village planning structures, convergence mechanisms and digital governance systems – were shaped by feedback from States and by lessons drawn from years of implementation.

An increase in allocations, equity
The broader premise that the employment guarantee was systematically weakened over the past decade does not align with facts. Budgetary allocations increased from ₹33,000 crore in 2013-14 to ₹86,000 crore in 2024-25. Person days generated rose from 1,660 crore in the period up to 2013-14 to 3,210 crore thereafter. Central funds released increased from ₹2.13 lakh crore to ₹8.53 lakh crore, and completed works expanded from 153 lakh to 862 lakh. Women's participation rose from 48% to 56.73%. Over 99% of fund transfer orders are now generated on time, and nearly 99% of active workers are linked to the Aadhaar Payment Bridge. These trends point to sustained commitment and improved delivery, not neglect.

What became evident over time, however, was that implementation experience had also revealed structural weaknesses in the earlier framework itself – episodic employment, weak enforceability of unemployment allowance, fragmented asset creation and persistent scope for duplication and ghost entries. These weaknesses were visible on the ground during drought years, migration spikes and periods of disruption such as the COVID-19 pandemic.

Fiscal restructuring under the new Act is also mischaracterised as abdication. The central government's contribution is increasing – the provision for the Centre's share rises from ₹86,000 crore to nearly ₹95,000 crore, underscoring continued and enhanced support for rural employment. The 60:40 funding model follows the long-established structure of centrally sponsored schemes, while the northeastern and Himalayan States and Jammu and Kashmir are accorded a differential 90:10 ratio. Far from signalling fiscal withdrawal, this framework reinforces shared responsibility and accountability.

Equity is ensured through rule-based normative allocation, with State-wise allocations determined on objective parameters prescribed in the Rules. States are treated not as mere implementing agencies but as partners in development, empowered to notify and operationalise their own schemes within the statutory framework. Flexibility is explicitly preserved: during natural disasters, or other extraordinary situations, States may recommend special relaxations, which includes expansion of employment. Rule-based allocation and operational flexibility are thus balanced in a manner consistent with cooperative federalism. The Act empowers States to notify, in advance,

periods aggregating to 60 days in a financial year covering peak sowing and harvesting seasons during which works shall not be undertaken. Differentiated notifications may be issued at the level of districts, blocks, or gram panchayats based on agro-climatic conditions, ensuring that the enhanced employment guarantee complements agricultural operations.

The UPA's record
From its very first tenure, the Congress-led United Progressive Alliance (UPA) government failed to match rhetoric with delivery under MGNREGA. While the Congress manifesto promised "at least 100 days of work at a real wage of ₹100 per day", the government capped wages at ₹100 as early as 2009 and kept them frozen for years, ignoring inflation and rising rural distress. The Centre openly admitted that States were acting arbitrarily under the scheme and justified the wage freeze by blaming State governments for 'indiscriminate increases'. This admission itself exposed a serious governance failure: the Congress-led Centre was unable to control even its own State governments, allowing MGNREGA to become vulnerable to misuse, fake job cards, and financial leakages.

The UPA's second term saw a steady decline in commitment to the scheme. Budgetary allocations were cut from ₹40,100 crore in 2010-11 to ₹33,000 crore by 2012-13, despite growing demand from States. In a parliamentary reply in 2013, Minister of State Rajeev Shukla acknowledged that employment under MGNREGA had fallen sharply – from 7.55 crore workers in 2010-11 to just 6.93 crore by November 2013. Delayed fund releases, lack of transparency in payments, and administrative apathy discouraged workers from seeking employment, directly undermining the legal guarantee promised under the Act.

The Comptroller and Auditor General's 2013 report laid bare the true state of MGNREGA during the UPA years. It highlighted widespread corruption and mismanagement: over 4.33 lakh fake or defective job cards, thousands of crores lost to unaccounted withdrawals and irregular work, delayed or denied wages in 23 States, and poor record-keeping in more than half of India's gram panchayats. States with the highest concentration of rural poor – Bihar, Uttar Pradesh and Maharashtra – used only about 20% of allocated funds, proving that the scheme failed precisely where it was needed most.

To frame the debate as a choice between welfare and development is to pose a false dichotomy. Welfare, when anchored in a guaranteed livelihood, and development, when anchored in durable rural infrastructure and productivity, are not competing objectives but interdependent ones. The real decision was whether to freeze a framework that often under-delivered, or to reform it into a modern, enforceable, and integrated employment guarantee that advances welfare through development. The new Act preserves the legal right to work, expands entitlements, strengthens worker protections, and corrects structural weaknesses revealed through years of implementation. This is not demolition, but a process of renewal grounded in experience.

जीएस पेपर 2: शासन

यूपीएससी मुख्य अभ्यास प्रश्न : "वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 राहत-उन्मुख रोजगार गारंटी से आगे बढ़कर विकास-आधारित, अधिकार-आधारित ग्रामीण आजीविका ढांचे की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। इस कथन की आलोचनात्मक जांच करें। अपने उत्तर में, चर्चा करें कि विकेंद्रीकरण, राजकोषीय जिम्मेदारी और सहकारी संघवाद को संतुलित करते हुए अधिनियम पहले के ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों की संरचनात्मक कमजोरियों को कैसे दूर करता है। (150 शब्द)

संदर्भ :

विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G ACT) को स्वीकृति भारत के ग्रामीण रोजगार और आजीविका ढांचे में एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार का प्रतीक है। शिवराज सिंह चौहान द्वारा व्यक्त इस अधिनियम का उद्देश्य वैधानिक मजदूरी रोजगार, टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण, कृषि उत्पादकता और आजीविका विविधीकरण को एकल, अधिकार-आधारित ढांचे में एकीकृत करके कल्याण की एक संकीर्ण अवधारणा से आगे बढ़ना है। रोजगार गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है और अभिसरण आधारित योजना को शामिल करके, अधिनियम पहले की व्यवस्थाओं के तहत लंबे समय से चले आ रहे कार्यान्वयन अंतराल को दूर करने का प्रयास करता है।

मुख्य प्रावधान और आशय

काम करने के कानूनी अधिकार का विस्तार और सुदृढीकरण

- वैधानिक रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिससे इसका न्यायोचित स्वरूप बरकरार रहेगा।
- प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करना जो पहले बेरोजगारी भत्ते तक पहुंच को कम करते थे।
- कानूनी वादे और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को दूर करते हुए समयबद्ध शिकायत निवारण को मजबूत किया गया।

संकटग्रस्त से लेकर अग्रिम रोजगार तक

- काम की मांग श्रमिकों से उत्पन्न होती रहती है, लेकिन अग्रिम रूप से, भागीदारी ग्राम-स्तरीय योजना मांग किए जाने पर काम की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।
- यह प्रतिक्रियात्मक राहत से निवारक आजीविका सुरक्षा की ओर रूपरेखा को बदल देता है, जो विशेष रूप से सूखे, प्रवासन में वृद्धि और महामारी जैसे झटकों के दौरान प्रासंगिक है।

संरचित समन्वय के साथ विकेंद्रीकरण

- ग्राम पंचायतें और ग्राम सभाएं प्राथमिक योजना और अनुमोदन प्राधिकरण बने हुए हैं।
- जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एकत्रित विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं की शुरूआत।
- केंद्रीकरण सुसंगतता और अभिसरण तक सीमित है, निर्णय लेने तक नहीं, सहकारी संघवाद के साथ संरचित करना।

राजकोषीय संरचना और इक्विटी

- राजकोषीय निकासी के दावों का मुकाबला करते हुए केंद्रीय आवंटन बढ़कर लगभग 95,000 करोड़ रुपये हो गया।
- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों और जम्मू और कश्मीर के लिए 90:10 के साथ 60:40 केंद्र-राज्य वित्त पोषण पैटर्न को बनाए रखा गया है।
- नियम-आधारित मानक आवंटन अंतर-राज्य समानता सुनिश्चित करता है, जबकि आपदा स्थितियों और असाधारण परिस्थितियों के लिए लचीलापन बनाए रखा जाता है।

कृषि और आजीविका के साथ अभिसरण

- राज्यों को कृषि के साथ पूरकता सुनिश्चित करते हुए चरम बुवाई/कटाई के मौसम के दौरान 60 दिनों तक का अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है, जब कार्य शुरू नहीं किया जाएगा।
- प्रासंगिक रोजगार के बजाय टिकाऊ परिसंपत्तियों, उत्पादकता में वृद्धि और आजीविका विविधीकरण पर जोर।

आलोचनाओं को संबोधित करना

- मांग-संचालित प्रकृति का कमजोर पड़ना: अधिनियम मांग-आधारित रोजगार को नहीं छोड़ता है; यह तैयारी और योजना के माध्यम से मांग को संचालित करता है।

- केंद्रीकरण: निर्णय लेने वाला प्राधिकरण स्थानीय रहता है; विखंडन को कम करने के लिए सभी क्षेत्रों में समन्वय का केंद्रीकरण किया गया है।
- परामर्श की कमी: सुधार में राज्यों के साथ व्यापक परामर्श, तकनीकी कार्यशालाओं और हितधारकों की चर्चाओं के बाद किया गया, जो कार्यान्वयन के वर्षों के अनुभव पर आधारित है।

तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य: पिछली सीमाओं से सीखना

- पहले के मनरेगा ढांचे के तहत कार्यान्वयन के अनुभव से संरचनात्मक कमजोरियों का पता चला - प्रासंगिक रोजगार, बेरोजगारी भत्ते की कमजोर प्रवर्तनीयता, खंडित परिसंपत्ति सृजन और लीकेज की गुंजाइश। ऑडिट के निष्कर्षों और उपयोग पैटर्न ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संस्थागत रीडिजाइन के बिना केवल वैधानिक इरादा परिणामों की गारंटी नहीं दे सकता है, खासकर गरीब राज्यों में। VB-G RAM G ACT एक खराब प्रदर्शन करने वाली संरचना को प्रीज करने के बजाय सीखे गए सबक को संस्थागत बनाने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।

निष्कर्ष

वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 ग्रामीण रोजगार को अल्पकालिक सुरक्षा जाल से ग्रामीण विकास के भीतर अंतर्निहित एक व्यापक, लागू करने योग्य आजीविका गारंटी में बदल देता है। अधिकारों का विस्तार करके, विकेंद्रीकृत योजना को मजबूत करके, राजकोषीय प्रतिबद्धता सुनिश्चित करके और कृषि और बुनियादी ढांचे के साथ अभिसरण को बढ़ावा देकर, अधिनियम कार्यान्वयन के वर्षों में उजागर संरचनात्मक अंतराल को ठीक करने का प्रयास करता है। सुधार कल्याण बनाम विकास के द्विआधारी को चुनौती देता है, इसके बजाय यह दावा करते हुए कि टिकाऊ विकास कल्याण का सबसे मजबूत रूप है। हालांकि, इसकी अंतिम सफलता प्रभावी राज्य क्षमता, कार्यान्वयन में पारदर्शिता और अधिकार-आधारित ग्रामीण परिवर्तन के लिए निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी।